

हरदा कलेक्ट्रेट कार्यालय के भाईसी कक्ष में वचुअल पापण कार्यक्रम को देखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने कहा है कि हमारा देश में बसता है। अधोसंरचना में कार्य से आर्थिक विधियों को बल मिलेगा और नए दिक्कों को दूर किया जा सकेगा। विशेषकर सड़कों का बिछाने से विकास की राह नए हो रही है। श्री चौहान ने मिंटो हॉल में ग्रामीण विकास सभागार में लगभग 13 ग्रामीण सड़कों का वचुअल पापण किया। कार्यक्रम में जिले की विदेशी वर्ष 0-21 में पूर्ण 695.93 रुपये की लागत से निर्मित 33 सड़कों का लोकार्पण किया।

आखिर मिली जमानत



इस मामले में करीब एक महीना जेल में बिताने के बाद ऐक्ट्रेस रिया च वर्ती को आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बॉलिवुड ऐक्टर सुशंत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत ने न केवल ऐक्टर के मित्रों-परिजनों और उनके लाखों प्रशंसकों को बल्कि दो राज्यों की पुलिस और सरकार के साथ-साथ कई केंद्रीय एजेंसियों को भी लंबे समय तक उलझाए रखा है। सुशंत के रूप में एक प्रतिभाशाली अभिनेता का असमय जाना विश्वय ही दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन इस घटना के बाद विभिन्न तबकों से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं और फिर घटना म जैसा बनता गया, उस पर बाद में ठहरकर सोच-विचार करना होगा। फिलहाल यहां इतना ही कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह सारा ध्यान एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया, उससे एक गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अभी काफी हद तक स्पष्ट हो गया है कि सुशंत सिंह राजपूत के साथ लगभग एक साल से लिंव-इन में रह रही उनकी गर्लफ्रेंड रिया च वर्ती पर कुछ ऐसे आरोप भी लगाए गए जिनका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। हत्या और पैसे की हेराफेरी के आरोपों की जांच के म में कुछ पुराने वॉट्सऐप चैट्स के जरिए उन पर इग्स खरीदने में प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका निभाने के नए आरोप लगे, जिनमें उनकी गिरफ्तारी हुई और जमानत न मिलने की वजह से एक महीना जेल में रहना पड़ा। इग्स से जुड़े मामलों में कई हाईकोर्ट अतीत में यह व्यवस्था दे चुके हैं कि अगर जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा ज्यादा न हो और व्यावसायिक इस्तेमाल का मकसद न पुष्ट हो रहा हो तो जमानत दे दी जानी चाहिए। एक परखवाड़ा भी नहीं हुआ जब स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने मुंबई में ही कथित तौर पर नशे के कारोबार से जुड़े तीन लोगों को इस आधार पर जमानत दे दी कि उनके पास से बरामद माल की मात्रा मध्यम (इंटरमीडिएट) थी। लेकिन रिया च वर्ती के पास से तो इग्स की कोई भी मात्रा बरामद नहीं हुई थी। बावजूद इसके उनके खिलाफ कानून की इतनी कड़ी धाराएं लगाई गई कि निचली अदालतों के लिए जमानत देना मुश्किल हो गया। आम धारणा यही है कि जिन मामलों में अपराध गंभीर न हो और सबूतों से छेड़छाड़ का डर न हो, उनमें जमानत देने पर उदारता से विचार होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत देकर इस मामले में अच्छी मिसाल पेश की है। जमानत के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जोड़कर हाईकोर्ट ने इस आशंका को लगभग समाप्त कर दिया है कि बाहर आने के बाद रिया गवाहों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसके बावजूद एनडीसीबी ने संकेत दिया है कि इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। बेशक उसे ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकारी एजेंसी को अपने कार्यों से समाज में ऐसा कोई संदेश नहीं जाने देना चाहिए कि वह किसी खास व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है।

अमेरिकी चुनाव

अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद भी बेहद अहम

अमेरिकी संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए दो भूमिकाएं तय की हैं - उपराष्ट्रपति अमेरिकी सिनेट का प्रमुख होता है और वोटिंग में टाई की स्थिति होने पर उसका वोट टाई-ब्रेकर होता है. और दूसरी भूमिका ये कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति पद का पहला उत्तराधिकारी होता है.

इस बार के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरीं भारतीय मूल की कमला हैरिस को लेकर भारत में काफी उत्सुकता है. लेकिन उनके इस चुनाव में उतरने की क्या है अहमियत? वो क्या कर पाएंगी एक उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर वो चुनी जाती हैं? क्या जिम्मेदारियां या ताकत होगी उनके पास? उपराष्ट्रपति पद के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों और मौजूदा स्थिति के बारे में हमने बात की जोएल सी इम्मेल से जो सेंट लुई युनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर ऑफ लॉ एमिरेटस हैं. प्रोफेसर इम्मेल के मुताबिक अमेरिकी संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए दो भूमिकाएं तय की हैं - उपराष्ट्रपति अमेरिकी सिनेट का प्रमुख होता है और वोटिंग में टाई की स्थिति होने पर उसका वोट टाई-ब्रेकर होता है. और दूसरी भूमिका ये कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति पद का पहला उत्तराधिकारी होता है. अधिकतर 19वीं सदी और आधी 20वीं सदी तक उपराष्ट्रपति की सिनेट के बाहर कोई भूमिका नहीं होती थी. पार्टी उन्हें चुनती थी और कई बार उनकी राय राष्ट्रपति से मिलती नहीं थी. उनके ना कोई खास योग्यता होती थी ना नामी गिरामी होते थे. लेकिन ये हालात तब बदलने शुरू ये हालात भी इसलिए बदले क्योंकि उस वक्त दुनिया में काफी कुछ बदला. अमेरिका में न्यू डील यानी आर्थिक पुनरुत्थान की कोशिशें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय सरकार सबसे अहम हो गई. ये वक्त शीत युद्ध का भी था और रूस को टक्कर देने के लिए उपराष्ट्रपति पद पर एक ऐसे शख्स का होना जरूरी था जो एटॉमिक एज में देश का पक्ष दूसरे देशों के सामने रख सके, जिसे इन विषयों की जानकारी हो और जिसकी इज्जत हो. राष्ट्रपति इवाइट सी आइजनहावर निक्सन को दूत के तौर पर अंतरराष्ट्रीय दौरों पर भेजा करते थे, निक्सन सुरक्षा बैठकों में शामिल होते थे, कमेटियों के प्रमुख होते थे. निक्सन के दौर में उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद के लिए सबसे अहम शुरुआत बन गया।

भारत और बर्मा यानी म्यांमार

पर पहले ब्रिटिश राज था. बौद्ध

धर्म भारत से ही बर्मा में गया

है और मुगलों के आखिरी

बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के

आखिरी दिन उसी देश में

गुज़रे थे और उनकी क़ब्र भी

वहीं है. बर्मा में आठ नवंबर को

आम चुनाव हैं. हो सकता है कि

भारत से दोस्ती बढ़ाने का

काम चुनाव तक ही जारी रहे.

कुछ विशेषज्ञ ऐसा ही मानते हैं.

वो कहते हैं, फ़ चुनाव के बाद

बर्मा एक बार फिर से चीन की

गोद में जा गिरेगा. फिलहाल

रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर बर्मा

से दुनिया के कई देश नाराज़

हैं, जिसके कारण उसकी

निर्भरता चीन पर बढ़ी है. और

अब जब भारत ने एक नई

पहल की है तो इसका बर्मा ने

स्वागत किया है.

क्या बर्मा और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4-5 अक्तूबर को बर्मा के दौर पर थे. क्या ये इस बात का संकेत है कि दोनों पड़ोसी एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं? दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी नज़र आ रही है? बर्मा में भारत के पूर्व राजदूत राजीव भाटिया ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, «मैं समझता हूँ कि इस दौर का एक विशेष महत्व है. निस्संदेह इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मज़बूत होंगे. महत्वपूर्ण ये बात भी है कि भारत ने पहली बार विदेश सचिव और सेना प्रमुख को एक साथ बर्मा भेजा. इसकी वजह बताते हुए राजीव भाटिया कहते हैं, «इसके दो कारण हैं. पहला ये कि वहीं सत्ता बँटी हुई है, थोड़ी चुनी हुई सरकार के हाथों में है और थोड़ी सेना के हाथों में. वहाँ दो लीडर हैं, एक कमांडर इन चीफ़ और एक स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची हैं.' तो इसलिए भारत सरकार चाहती थी कि बर्मा सरकार के दोनों अंगों के नेताओं से मिला जाए. और दूसरा भारत की सेना और उसकी लीडरशिप के प्रति म्यांमार में बहुत सम्मान है. तो इसलिए ये समझा गया कि दोनों के जाने से एक अच्छा असर पड़ेगा. शायद इसीलिए बर्मा के साथ कुल तीन औपचारिक बैठकों में से दो में केवल सेना प्रमुख शामिल थे.

भारत के लिए क्षेत्र में सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके तार भी चीन से जुड़े हैं. वो इस तरह कि चीन के प्रांत युन्नान से शुरू होकर 1700 किलोमीटर लंबा आर्थिक कॉरिडोर बर्मा के दक्षिण-पश्चिमी इलाक़े तक आकर ख़त्म होता है, जो बंगाल की खाड़ी से लगा इलाक़ा है. इसका मतलब ये है कि सैद्धांतिक रूप से चीन की पहुँच बंगाल की खाड़ी तक आसानी से हो सकती है. ये आर्थिक कॉरिडोर, जिसमें चीन ने अरबों रुपए का निवेश कर रखा है, उसी तरह का कॉरिडोर है, जो भारत के पश्चिम में चीन और पकिस्तान को जोड़ता है. पकिस्तान और बर्मा वाले आर्थिक कॉरिडोर चीन की «बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव» का हिस्सा हैं, जो चीन को दुनिया से जोड़ते हैं. इसमें चीन ने अब तक अरबों डॉलर खर्च किया है. चीन ने बांग्लादेश के रास्ते भारत के साथ भी इसी तरह के आर्थिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने

मंज़ूर नहीं किया. इस आर्थिक कॉरिडोर का मक़सद व्यापार बढ़ाया जाता है. इसमें सैन्य एंगल नहीं है. लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार एक तरह से देखा जाए तो चीन ने भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर अपनी मौजूदगी बना ली है. 2017 में उत्तर में डोकलाम में और इस साल मई से लद्दाख़ में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है. उत्तर में नेपाल के अंदर भी चीन की लंबी पहुँच है.



राजीव भाटिया मानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है. शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की ऊर्जा बर्मा के साथ संबंध को मज़बूत करने में लगाई जा रही है.साल 2014 से अब तक भारत और बर्मा के नेताओं की सात आपसी यात्राएँ हो चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की बर्मा की दो और आंग सान सू ची की भारत की दो यात्राएँ शामिल हैं. भारत सालों से अफ़ग़ानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव की आर्थिक सहायता करता आया है. इन देशों के बुनियादी ढाँचों के प्रोजेक्ट्स भारत ने पूरे किए हैं और कई पर काम चल रहा है.महामारी के दौरान भी भारत ने इन देशों की दवाओं और मेडिकल किट से मदद की है. बर्मा में भी भारत के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और महामारी से लड़ने के लिए भारत मदद भी कर रहा है. लेकिन इसके बावजूद अब भी बर्मा का झुकाव चीन की तरफ़ अधिक है. दूसरे शब्दों में बर्मा चीन से भारत के मुक़ाबले में काफी नज़दीक है. चीन बर्मा में दशकों से काम कर रहा है.

इनमें घनिष्ठता उस समय बढ़ी, जब चीनी राष्ट्रपति इस साल जनवरी में बर्मा गए. राजीव भाटिया स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, चीन का मुक़ाबला भारत नहीं कर सकता.वो कहते हैं, «पिछले पाँच सालों में हालात बदले हैं, खास तौर से जब से 2016 में आंग सान सू ची चुनाव जीत कर आई हैं. बर्मा में चीन का अस्तित्व काफी बढ़ गया है. उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस साल जनवरी में चीन के राष्ट्रपति जब बर्मा गए थे, तो दोनों देशों के बीच 33 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए.»

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि बर्मा में आम सोच ये है कि भारत और चीन उन्हें आकर्षित करने के लिए मुक़ाबला करते रहे, तो फ़ायदा बर्मा को ही होगा. इसलिए दोनों में संतुलन बनाने पर उनका जोर होता है.

उधर इस सच से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि 1980 और 1990 के दशकों में भारत ने बर्मा के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखने पर जोर नहीं दिया और उसका मुख्य कारण था बर्मा में सैनिक शासन की स्थापना और लोकतंत्र का ख़त्म होना. भारत में लोकतंत्र फल-फूल रहा था, तो ज़ाहिर है इसने उस समय ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारों से दूरी बनाए रखी. बदलाव आया जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने. राजीव भाटिया बर्मा में भारत के राजदूत रहने के अलावा दोनों देशों के रिश्तों पर किताब भी लिख चुके हैं. वो इतने मायूस नहीं हैं. उनका कहना है कि सॉफ़्ट पावर में भारत अब भी चीन से आगे है.

भारत और बर्मा यानी म्यांमार पर पहले ब्रिटिश राज था. बौद्ध धर्म भारत से ही बर्मा में गया है और मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के आखिरी दिन उसी देश में गुज़रे थे और उनकी क़ब्र भी वहीं है. बर्मा में आठ नवंबर को आम चुनाव हैं. हो सकता है कि भारत से दोस्ती बढ़ाने का काम चुनाव तक ही जारी रहे. कुछ विशेषज्ञ ऐसा ही मानते हैं. वो कहते हैं, «चुनाव के बाद बर्मा एक बार फिर से चीन की गोद में जा गिरेगा. फिलहाल रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर बर्मा से दुनिया के कई देश नाराज़ हैं, जिसके कारण उसकी निर्भरता चीन पर बढ़ी है. और अब जब भारत ने एक नई पहल की है तो इसका बर्मा ने स्वागत किया है.

हाथरस: उप्र में बड़ी घटनाओं के पीछे ‘अंतरराष्ट्रीय साज़िश’ कैसे आ जाती है?

उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए कथित बलात्कार और फिर हत्या के मामले में पीड़ित युवती के परिजन जब न्यायिक जांच की मांग पर अड़े हैं वहीं पुलिस अब इस घटना को %इतना तूल% देने के पीछे अंतरराष्ट्रीय साज़िश की बात कह रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस का आरोप है कि राज्य में जातीय और सांप्रदायिक दंगे कराने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साज़िश रची गई थी. हाथरस के चंदपा थाने में इस संबंध में तीन दिन पहले एक नई एफ़आईआर दर्ज की गई जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ राजद्रोह जैसी धाराएं लगाई गई हैं. बुधवार को इस मामले में चार लोगों को मुख़्तार से गिरफ़्तार भी किया गया जिनमें मलयालम भाषा के एक पत्रकार भी शामिल हैं. हाथरस मामले में कथित अंतरराष्ट्रीय साज़िश के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में कम से कम 19 एफ़आईआर दर्ज की हैं और मुख़्त एफ़आईआर में करीब 400 लोगों के खिलाफ राजद्रोह, षडयंत्र, राज्य में शांति भंग करने का प्रयास और धार्मिक नफ़रत को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय के हवाले से मीडिया में ये ख़बरें भी चल रही हैं कि हाथरस की इस घटना को जातीय और सांप्रदायिक दंगों में बदलने के लिए मॉरीशस के ज़रिए करीब 100 करोड़ रुपये की फ़ंडिंग भी हुई है. हालांकि इसके न तो पुख़्ता सबूत मिले हैं और न ही आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हुई है.

पुलिस जिस संगठन पर शक़ ज़ाहिर कर रही है उसका नाम पीएफ़आई यानी पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया है और गिरफ़्तार किए गए लोगों के भी इस संगठन से संपर्क बताए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने इससे पहले नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ इस साल दिसंबर में हुए प्रदर्शनों और इस दौरान हुई हिंसा के लिए भी पीएफ़आई को ही जिम्मेदार ठहराया था. उस दौरान 100 से भी ज्यादा पीएफ़आई सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया था और मुख़्यमंत्री ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. यूपी में इससे पहले भी कुछ घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं जिनके तूल पकड़ने के बाद उनके %अंतराष्ट्रीय तार% जोड़ने की कोशिश की गई. स्थानीय घटनाओं में



अंतरराष्ट्रीय साज़िश की बात से हैरानी ज़रूर होती है लेकिन यूपी के मुख़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी कहते हैं कि इस साज़िश में कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता भी शामिल हैं. शलभमणि त्रिपाठी के मुताबिक, राज्य सरकार ने दंगाई मानसिकता के लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयां की हैं, उससे ऐसे संगठनों में बौख़लाहट है. उपद्रवियों के पोस्टर सरेआम चौराहों पर लगाए गए, उनकी संपत्तियां कुर्क करके सार्वजनिक नुक़सान की वसूली भी की गई.

ऐसे में पीएफ़आई जैसे संगठनों ने योगी सरकार को बदनाम करने और प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगे कराने की साज़िश रची. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कुछ राजनीतिक दल भी अराजकता की इस साज़िश में पीएफ़आई जैसे संगठनों के साथ खड़े दिख रहे हैं. नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ राज्य में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे और उस दौरान लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, फ़िरोज़ाबाद, मेरठ जैसे कई शहरों में हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी और सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठे थे. सरकार ने प्रदर्शनों के आयोजन और उस दौरान हिंसा होने की घटना को भी अंतरराष्ट्रीय साज़िश बताया था. वरिष्ठ

पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस इन घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय साज़िश की बजाय 'प्रशासनिक नाकामी को ढकने की कोशिश' मानते हैं. सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, «हाथरस में जो कुछ भी हुआ है वह प्रशासनिक नाकामी और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. सुप्रीम कोर्ट में भी इस नाकामी को ढकने के जो तर्क दिए गए हैं वो बेसिर-पैर के हैं. चूकि प्रशासनिक नाकामी आख़िरकार सरकार की ही नाकामी की तरह है, इसलिए उसे ढकने के लिए अब अंतरराष्ट्रीय साज़िश की ढ़ाल तैयार की जा रही है.» यूपी के डीजीपी रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय हाथरस जैसी घटनाओं के पीछे अंतरराष्ट्रीय साज़िश जैसी बात को सिरे से नकारते हैं.

बीबीसी से बातचीत में डॉक्टर वीएन राय कहते हैं, «इसमें कोई तथ्य नहीं है. सिर्फ़ गुमराह करने की कोशिश है. आप देखिएगा, दो-चार हफ़्ते के बाद ये सारी साज़िशें कहीं नहीं दिखेंगी. सब भूल जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय साज़िश के जो प्रमाण दिए जा रहे हैं वो शुरुआती दौर में ही इतने खोखले हैं कि कोर्ट पहुंचने से पहले ही धराशायी हो जाएंगे.» लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय साज़िश की बात कहने के पीछे क्या सच में लोगों को गुमराह करना या फिर %समय काटना% है या

फिर इसके पीछे कुछ राजनीतिक नफ़े-नुक़सान का गणित भी काम करता है. इस सवाल के जवाब में सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, «निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान तो बंटेंगा ही. लोग अब एक नए एंगल की थ्योरी पर सोचना शुरू कर देंगे और उन्हें लगेगा कि हां, सच में ऐसा हो रहा है. दूसरे, अंतरराष्ट्रीय साज़िश में सीधे तौर पर इस्तेमालिक देशों का ज़िक्र किया जा रहा है तो ऐसी बातों में बीजेपी अपना फ़ायदा ही देखती है.%

'विरोधी को तो वो अपने पक्ष में ला नहीं सकते हैं लेकिन जिन समर्थकों का विश्वास सरकार की कार्यशैली से उठने लगा है, ऐसी साज़िशों का ज़िक्र करके वो कुछ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके, उनका विश्वास एक बार फिर जीतने की कोशिश तो हो ही सकती है.» खुफ़िया एजेंसियों को खबर क्यों नहीं?

हालांकि यदि अंतरराष्ट्रीय साज़िश की बात मान भी ली जाए, तो अहम सवाल यह भी उठता है कि इसी न बड़ी साज़िश हो रही थी तो पुलिस या खुफ़िया एजेंसियों को पता क्यों नहीं चला? और उन्हें पहले ही रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई. सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन को भी अंतरराष्ट्रीय साज़िश से जोड़ा गया लेकिन न तो कोई पुख़्ता सबूत मिले और न ही किसी के ख़िलाफ़ अब तक कोई चार्ज शीट फ़ाइल की जा सकी है. शलभ मणि त्रिपाठी कहते हैं, «सीएए प्रदर्शन के दौरान भी पूरे देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार की मुस्तेदी और खुफ़िया तंत्र की सक्रियता के चलते पूरे प्रदेश में एक भी बेकसूर व्यक्ति को इस उपद्रव से नुक़सान नहीं पहुंचा. शलभ मणि त्रिपाठी का दावा है कि सीएए प्रदर्शन के दौरान एक भी बेकसूर व्यक्ति को नुक़सान नहीं हुआ लेकिन प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई और उससे जुड़े कई मुक़दमे अभी अदालत में लंबित हैं. जहां तक हाथरस की घटना का सवाल है, राज्य सरकार ने चार दिन पहले ही उसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफ़ारिश की थी लेकिन उसकी स्वीकृति अब तक नहीं मिली है. दूसरी ओर, जांच का दायरा अब गैंगरेप और हत्या के अलावा अंतरराष्ट्रीय साज़िश के साथ-साथ युवती की मौत की अन्य वजहों की ओर भी मुड़ता दिख रहा है.

निराशा के घटाटोप में सोने के भंडार की चमक

(राकेश दुबे)

वैसे तो मार्च के बाद हर दिन उगने-डूबने वाला सूरज एक निराशा के साथ अस्ताचल को जाता था 7 आगे क्या होगा ? का सवालिया निशान अपना दौदा मुंह खड़े खड़ा रहता था 7 इसी दौरान 25 सितंबर 2020 को रिजर्व बैंक के आंकड़ों से आई खबर ने राहत दी है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 542 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें 653 मीट्रिक टन सोने का भंडार भी शामिल है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम योगदान होता है। याद कीजिये, वर्ष1991 में जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे, तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। तब देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रख कर कर्ज लिया था।आज सोने के भंडार के मद्देनजर भारत दुनिया में 9 वें स्थान पर है और विदेशी मुद्रा भंडार की ऊंचाई भारत के लिए लाभप्रद दिखती है। इस

यात्रा की शुरुआत भी वर्ष 1991 में नयी आर्थिक नीति से हुई, जिसका उद्देश्य वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ाना रहा। इस नीति के पश्चात धीरे-धीरे देश के भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरने लगी। वर्ष 1994 से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। 2002 के बाद इसने तेज गति पकड़ी। वर्ष 2004 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा। फिर इसमें लगातार वृद्धि होती गई और 5 जून, 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार ने 501 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को प्राप्त किया। 25 सितंबर 2020 को542 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच चुके विदेशी मुद्रा भंडार के और बढ़ने की संभावनाए दिख रही हैं।भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने के अनेक कारण हैं। दुनिया भर के बड़े देशों के सेंट्रल बैंकों ने जिस तरह अपने विदेशी मुद्रा कोष में गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है, उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी वर्ष 2018 से गोल्ड रिजर्व

तेजी से बढ़ाया है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोल्ड रिजर्व करीब 653 मीट्रिक टन के स्तर पर है, पर खर्चों पर भी ध्यान जरूरी है।भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है और इस पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमी विदेशी मुद्रा भंडार के लिए लाभप्रद रही है। देश में कोविड–19 के कारण मार्च2020 से लागू लॉकडाउन की वजह से जून 2020 तक पेट्रोल–डीजल की डिमांड कम हो गई थी, इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट ने भी विदेशी मुद्रा भंडार के व्यय में कमी की है। इसी तरह सोने के आयात में लगातार कमी से भी विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी आई है। देश के आयात बिल में सोने के आयात का प्रमुख स्थान है। पिछले वित्त वर्ष 2019 –20 में सोने का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हुई है।

सरकार ने आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के भी कई कदम उठाए हैं। इससे देश के विदेश व्यापार घाटे की चुनौती में कमी आई है और विदेशी मुद्रा भंडार को लाभ हुआ है। खासतौर से चीन से आयात कम हुए हैं और चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी आने से भी विदेशी मुद्रा भंडार लाभान्वित हुआ है। देश में लॉकडाउन के कारण विभिन्न वस्तुओं की मांग में गिरावट के चलते आयात भी काफी कम हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार से कम व्यय करना पड़ा है।

कोविड–19 के दुष्फाल के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के इस ऊंचाई पर पहुंचने से भारत के लिए कई लाभ चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोविड–19 की अकल्पनीय आपदा से बेहतर ढंग से निपटने में विदेशी मुद्रा भंडार की प्रभावी भूमिका है। दुष्फाल से निबटने में यह भंडार देश के काम आये सरकार को इस ओर गंभीरता से सोचना चाहिए।

जैन के जीवन कार्यपालन संघों सीएम जानसपाल, रातोले शर्मा, स्वयं संघों जगदे, सिंह, सुनिल सिंह, उपर्योगदेश जैन, अनिल जानसपाल, मोना कोशे, राहुल शर्मा अजीविपत मिशन सिरी मैनेज, अतमिका पैर, ऑपत प्रभाश, राजाज्य अधिपति जगदेस पाटक, अनिल विपति, प्रभात कर्माणि अजीविपत नारेड, पैरले, खाद्य शाखा

सड़कों के जाल से हो रही विकास की राह आसान : मुख्यमंत्री

स्वराज्य अभियान,भोपाल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में श्रमिकों और किसानों सहित नागरिकों की तकलीफें दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। हमारा देश गांव में बसता है। अधोसंरचना क्षेत्र में कार्य से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और वर्तमान दिक्कों को दूर किया जा सकेगा। विशेषकर सड़कों का जाल बिछाने से विकास की राह आसान हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिटो हॉल में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित लगभग 13 हजार ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल



लोकार्पण कर रहे थे। लोकार्पित सड़कों में उप चुनाव वाले जिलों की सड़कों को लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में बनी ग्रामीण सड़क कार्यों की सराहना करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से आम लोगों की जिन्दगी बदलती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों स्. अटल जी ने देश में वृहद स्तर पर सड़कों के निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी इस दिशा में रुचि लेकर सड़कों के निर्माण के कार्यों को गति देने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सड़कों के साथ ही ग्रामों में आवास क्षेत्र में भी अधिकाधिक कार्य कर उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मार्च में कोरोना संक्रमण के उपचारी की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गईं। इस संकट के समय

में स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों की रोजी-रोटी की समस्या को दूर करते हुए उन्हें विभिन्न कार्यों से संलग्न किया गया। रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में मास्क, साबुन और सेनेटाइजर का निर्माण कर कोरोना के विरुद्ध अपनी भागीदारी दर्ज की। किसान कल्याण के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के द्वार खोल दिए। जरूरतमंदों को राशन मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याण के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देगी। ऐसे कार्यों के लिए धनराशि की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेत सड़क योजना पर ध्यान देंगे। इससे किसान अपनी मेहनत से उगाए उत्पादन को विक्रय के लिए आसानी से भेज सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कोरोना से अपना बचाव करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फिलहाल फेस मास्क ही वैक्सीन है। प्रत्येक व्यक्ति अपना बचाव करे, सावधानी में ही सुरक्षा है।

कोरोना काल में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 4 हजार 120 किलो मीटर लंबी 12 हजार 960 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवा कर आपदा को अवसर में बदला। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यह सड़कें 1359 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हुई हैं। लोकार्पण वाले 33 जिलों में 4.83 लाख कार्यों में 46.39 लाख श्रमिकों को नियोजित किया गया। कुल 11.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। कोरोना आपदा काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ विकास प्रक्रिया सतत जारी रखते हुये ये सड़कें बनाई गईं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 15 लाख श्रमिक दिवस सृजित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1104 किलो मीटर लम्बी 171 सड़कें एवं 47 बड़े पुल शामिल हैं। इनकी लागत 691.41 करोड़ रुपये है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने इस अवधि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 3016 किलो मीटर लंबाई की सीमेंट कांरीट की 10 हजार 792 सड़कें तथा

ग्रामों के भीतर स्कूल, मजरे-टोलों आदि में सुगमता से आने-जाने के लिये 1997 ग्रेवेल भी निर्मित कीं, जो ग्रामवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की पंचायत पदाधिकारियों से बातचीत

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पण के बाद कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। इनमें श्री कैलाश राठौर ग्राम पंचायत पलसोडा जनपद एवं जिला रतलाम, श्री राजेन्द्र पटेल उप प्रधान ग्राम पंचायत फुलरी जनपद चावरपाठा जिला-नरसिंहपुर और श्रीमती सेवती गणेश उइके प्रधान ग्राम पंचायत शोभापुर जनपद घोडाडोंगरी जिला बैतूल शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों को कम समय अवधि में संपन्न निर्माण कार्यों के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की और ग्राम में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति और कोरोना से बचाव के लिए अपनाए गए उपायों की भी जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।

मिटो हॉल स्टूडियो में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में सड़कों के निर्माण पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री सचिन सिन्हा, आयुक्त राज्य रोजगार गारंटी परिषद सोफिया फारूकी वली, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खांडे भी उपस्थित थे।

कांग्रेस ने की ग्वालियर और चंबल जनता के साथ गद्दारी : सिंधिया



स्वराज्य अभियान,ग्वालियर

कांग्रेस ने ग्वालियर और चंबल के साथ ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश के साथ गद्दारी की है। यह कहना है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वह यहां महाराजपुरा विमानतल तल पर मुरैना के दौरे पर निकलने से पहले पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा उनके ऊपर पार्टी के साथ गद्दारी किए जाने के आरोप के सवाल पर जवाब देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि विकास और

प्राप्ति के मामले में कमलनाथ और उनकी सरकार ने पूरे प्रदेश को धोखा दिया।

पूर्व सीएम कमलनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए श्री सिंधिा ने कहा कि उनको पूरे कार्यकाल में केवल अपनी कुर्सी और तिजोरी की चिंता रही। वहीं दूसरी

तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पांच महीने के कार्यकाल में जनता के हित में अपनी तिजोरी खोल दी। उन्होंने जनता के लिए अनेक योजनाएं दी हैं। वहीं कमलनाथ जी सदैव 'पैसा नहीं है' का रोना रोते रहे। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संभव को भी असंभव बना देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो असंभव को संभव करके दिखा देते हैं।

श्री सिंधिया ने कल एक रैली में कमलनाथ के काफिले पर हुए कथित हमले को निंदनीय बताते हुए कहा कि राजनीति में हम आमने-सामने जरूर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने राजनीति का जो स्तर दिखाया है उस पर उसे खुद भी अपने गिरेबां में झांकर देखना चाहिए।

आर.ओ. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान केन्द्र के अन्तर्गत संपूर्ण जानकारी लिखवायें: जिला निर्वाचन अधिकारी

मुरैना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने जिले के जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसरों को निर्देश दिये कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त जानकारी प्रिन्ट करावें। जिसमें दीवार या बैकग्राउण्ड पीले कलर का तथा अक्षर काले कलर के होने चाहिये। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, नाम, मतदान केन्द्र क्रमांक, मतदान केन्द्र का नाम, सम्मिलित क्षेत्र, मतदान दिनांक, मतदान का समय, रिटर्निंग ऑफीसर का नाम, मोबाइल नम्बर, बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर तथा थाना प्रभारी का मोबाइल नम्बर होने चाहिये।

भोज, महू और शहडोल विवि के कुलपति भी कर पाएंगे रैक्टर की नियुक्ति

राज्यपाल की मोहर का इंतजार

स्वराज्य अभियान, भोपाल

भोज विश्वविद्यालय, महू विश्वविद्यालय और शहडोल विश्वविद्यालय में भी रैक्टर की नियुक्ति हो सकेगी। विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 में यह प्रावधान किए जा रहे है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों का हवाला देते हुए भोज विश्वविद्यालय ने यह प्रस्ताव दिया था, जिसको स्थाई समिति ने मंजूरी दे दी है। अब विश्वविद्यालय समन्वय समिति की मंजूरी के बाद उक्त विश्वविद्यालयों में रैक्टर की नियुक्ति हो सकेगी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को रैक्टर नियुक्त करने का अधिकार होता है। कुछ दिनों पहले बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलनति आरजे राव ने डीन केबी पंडा को बीयू का रैक्टर नियुक्त किया है।

इसके अलावा अस्थाई समिति ने अन्य कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत अब विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को कोड 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करना होगी। यह प्रावधान पहले से है। इसके बाद भी कॉलेजों में कोड 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है। इसको देखते हुए अब इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी विश्वविद्यालयों को करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वहीं पीएचडी की थीसिस को ऑनलाइन जमा किए जाने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। इससे पीएचडी में नकल सहित अन्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी शोधाधीन नहीं कर पाएंगे।

लंबे समय से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अधिनियम में एकरूपता लाने की बात चल रही है। इसको लेकर एक बार फिर स्थाई समिति ने मंजूरी दी है। इसका प्रस्ताव समन्वय समिति में रखा जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा और परीक्षा परिणाम एक ही समय पर आएंगे। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सभी सामनता होगी। एक समय पर होंगे सभी विवि के एजाम।



सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित हो सकेंगे : डॉ. राजौरा

स्वराज्य अभियान, भोपाल

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विधानसभा उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रों में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में गृह विभाग द्वारा भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा आवेदन पर विचार करने के बाद कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी हालत में उक्त कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।

कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लंघित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरुद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

व की तीन लाख रिक्त सीटों पर प्रवेश देने कल से तीसरी एस्टट होगी शुरू

भोपाल। प्रदेश के 1405 निजी और सरकारी कालेजों के यूजी की करीब तीन लाख रिक्त सीटों पर प्रवेश देने के लिए कल से तीसरी राउंड की कालेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) शुरू हो रही है। सीटों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि विभाग ने कालेजों को 15 से 30 अप्रैलटी तक सीटें बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत विद्यार्थी नौ से 14 अक्टूबर तक पंजीयन और च्वाइस फिलिंग कराएंगे। नये पंजीकृत विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक अपना सत्यापन कराएंगे। विभाग ने विद्यार्थियों को खास तौर पर सूचित किया है कि पूर्व की सभी च्वाइस फिलिंग निरस्त कर दी गई है। उन्हें तीसरे राउंड की सीएलसी में अपनी च्वाइस फिलिंग दोबारा देना होगी। 19 अक्टूबर को विभाग सभी की मोरिट जारी करेगा। मोरिट में स्थान वसतिन करने के बाद विद्यार्थी 26 अक्टूबर तक प्रवेश ले पाएंगे। इसी तरह पीजी में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी 14 से 19 अक्टूबर तक पंजीयन और च्वाइस फिलिंग कराएंगे।

अभियान

कोविड 19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान के दूसरे दिन

स्वराज्य अभियान, भोपाल

कोविड 19 अनुकूल व्यवहार सघन अभियान के दूसरे दिन आज प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्र और कार्यालयों में अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ ली गई।

कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान 30 नवम्बर तक

संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो श्री बसंत कुर्ने ने ब्यूरो कार्यालय में अधिकारियों के साथ अभियान के पहले दिन जिलों में संचालित की गई गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की। अभियान के क्रियावित्त करने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशो से सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराते हुए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए



दिए गए निर्देशो का पालन कर अभियान की गतिविधियों संचालित की जायें।

संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा ब्यूरो ने बताया कि आगामी दिनों में त्रौह्रर आदि के कारण लोगों के आपस में मिलने-जुलने और एकत्रित होने को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचाव के लिये दो गज की सामाजिक दूरी रखने, घर से बाहर निकलने पर मास्क

पहनने, साबुन-पानी से हाथ धोने अथवा सेनेटाइज करते रहने आदि जरूरी बचाव के उपायों को लोगों को बताया जाये। उन्होंने कहा कि अभियान की थीम 'सावधानी में ही सुरक्षा है' और पंचलाइन 'कोरोना से बचने के लिये है जरूरी, मास्क पहने, धोते रहें हाथ, रखें दो गज की दूरी' है। जिले के अन्य विभागों के कार्यालय प्रमुख संबंधित विभाग के लिये नोडल अधिकारी से संपर्क में रहें। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के लक्षण एवं बचाव की रोकथाम के उपायों से आमजन को परिचित करने के लिये प्रचार-प्रसार की उपयुक्त और व्यापक व्यवस्था करे। अभियान संचालन में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 संबंधी जानकारी और प्रचार सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर इसकी लिंक भेजी गई है। संचालक ने अभियान की प्रचार-प्रसार गतिविधियों की जानकारी सार्थक लाइट एप पर अपलोड करवाने के लिये भी अधिकारियों को कहा।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ली शपथ

कोविड 19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान के दूसरे दिन

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों के संबंध में आयोग के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के संबंध में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के लिये स्टार प्रचारकों की संख्येया 40 से घटाकर 30 कर दी गई है और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिये यह संख्या 20 से घटाकर 15 कर दी गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि सभी दल नामांकन की अधिसूचना दिनांक से अब 7 दिवस की बजाय 10 दिवस तक स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत कर सकेंगे। स्टार प्रचारकों की सभा या कार्यक्रम की अनुमति के लिये 48 घंटे पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।